आये दिन लुटते एटीएम बचाने के लिये इन्हें पुलिस चौकियों व थानों में लगाया जाये

फ़रीदाबाद (म.मो.) यूं तो जब-तब बैंकों के एटीएम लुटने के मामले सामने आते रहते हैं परन्तु बीते सप्ताह तो चार एटीएम लुट गये। एक एटीएम को तो जड़ से ही उखाड़ कर ले गये। जब से ये एटीएम लगे हैं, पहले से ही भारी दबाव में चल रही पुलिस पर काम का दबाव और बढ गया है।

10-20 लाख रुपयों से भरा, सड़क किनारे रखा एटीएम तो आपराधियों को आकर्षित करेगा ही। कहीं-कहीं इसकी रखवाली के लिये बैठा नकली सा गार्ड लुटेरों को रोक पाने में असमर्थ रहता है। पहले से ही घाटे में चल रहे एटीएम के धंधे पर कोई भी बैंक सही गार्ड व्यवस्था रखने पर अधिक खर्च करना नहीं चाहते। इस लिये सिक्युरिटी एजेंसियों के माध्यम से 8-10 हज़ार का गार्ड बैठा दिया जाता है जो अक्सर बूढा अथवा असहाय सा होता है। यदि किसी युवक को लगाते हैं तो वह दिन में कहीं अन्यत्र काम करता है और रात में एटीएम पर आकर नींद पूरी करता है।

इस समस्या पर यूनियन बैंक से जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुये एसपी गोयल से पूछा तो उन्होंने कहा कि बैंकों की आपसी स्पर्धा के चलते देश भर में 2 लाख 20 हज़ार से अधिक एटीएम खोल दिये गये हैं; इसके लिये सबसे पहले तो अनावश्यक एटीएम बंद कराये जायें। दूसरे रात्रि 9 या 10 बजे के बाद कोई एटीएम खुला नहीं रहना चाहिये जब तक कि वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था न हो। पुलिस परिसरों में एटीएम खोलने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे पुलिस के डर के मारे कोई ग्राहक एटीएम तक जायेगा ही नहीं।

यही सवाल सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक राजरूप सिंह व निरीक्षक प्रेम सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शहर में 25 थाने व 50 से अधिक पुलिस चौकियां हैं। इन सबका इस्तेमाल आवश्यकतानुसार इस काम के लिये किया जा सकता है। थाने या चौकी के गेट के पास एटीएम लगाये जायें तो इससे आये दिन होने वाली एटीएम वारदातें बिल्कुल बंद हो सकती हैं। इसके बदले बैंक सरकार/पुलिस विभाग को वही सब खर्चा अदा करे जो वे अब तक असुरक्षित एटीएम पर खर्च करके अपने एटीएम लुटवा रहे हैं।

नाम न छपने की शर्त पर एक बैंक अधिकारी ने यह भी कहा कि एटीएम लुटे या बैंक उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब का बीमा करा रखा है, जो भी नुक्सान होता है, बीमा कम्पनी से वसूल हो जाता है। क्या ही मजेदार बात है; बैंक या एटीएम में चोरी हो जाय या डकैती उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भागदौड़ करने, झाड़खाने व बदनामी झेलने के लिये सिर्फ़ पुलिस ही रह गयी है।

पुलिस की पोल न खुलवाओ

इसी विषय पर थानेदार से आईपीएस बनने तक का सफ़र तय कर चुके कुछ रिटायर लोगों से बात की तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यदि थाने-चौकियों से एटीएम उखड़ गये तो क्या होगा? फ़िर जो पुलिस की मिट्टी पलीत होगी उसका क्या होगा? उन्होंने दो उदाहरण भी दिये एक बार सोनीपत ज़िले के थाना राई व रोहतक के कलानौर थाने के बहुत ही निकट से एटीएम लुट गये थे तो उच्च स्तरीय मीटिंग में यह सुझाव आया था कि थाने-चौकियों के अहाते में ही एटीएम लगाया जाय। तब एक अधिकारी ने कहा कि जब सोते हुये संतरी की रायफ़ल उसकी चैकिंग करने वाला अफ़सर उठा कर ले जा सकता है तो फ़िर एटीएम क्या चीज़ है? और वह आइडिया वहीं ड्रॉप कर दिया गया।

संदर्भवश उन्होंने दो किस्से और बताये। इमरजेंसी के दौरान जब सोहना के रेस्ट हाउस में मोरारजी देसाई नज़रबंद थे। वे अपने नियमानुसयार प्रात: कालीन सैर के लिये निकले तो दोनों पहरेदार सिपाही सो रहे थे। देसाई जी ने उनकी रायफ़लें उठा कर अपने कमरे में छिपा दी और सैर को निकल गये। जब सिपाहियों की आंख खुली तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गयी। तुरंत आला अफ़सरों को सूचित किया गया। अफ़सर समझदार थे, वे उसी मार्ग पर दौड़े जिस पर वे नियमित सैर को जाते थे। वे मिल गये तो उनसे माफ़ी मांगी।

ऐसे ही एक बार तत्कालीन डीएसपी नरेंद्र अहलावत रात्रि गश्त चैक करते जब नीलम चौक पहुंचे तो जिप्सी में दो जवान ऊंची आवाज़ में संगीत बजा कर इतनी गहरी नींद सोये थे कि डीएसपी साहब दोनों की रायफ़लें उठा कर ले गये। जाहिर है इन हालात में अब पुलिस सुरक्षा भी बहुत विश्वसनीय नहीं रह गयी है।

रेन वाटर हार्वेसिटंग के बाद अब 74 तालाबों की घोषणा

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब तीन माह पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने शहर में 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की घोषणा की थी ताकि भूजल के गिरते स्तर को रोका जा सके। आज तक तो उनमें से एक भी न तो लगा है और न ही लगने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं। पूर्व पार्षद योगेश धींगड़ा ने अपने पल्ले से एक सिस्टम लगाने का प्रयास किया था, उसे भी अधबीच रूकबा दिया गया।

हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात छोड़ कर अब सरकार 74 उन पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने पर करोड़ों रुपया खर्च करने की बात कर रही है जिनमें सीवर का पानी व शहर का कूड़ा कचड़ा भर कर पहले तो सड़ाया गया फ़िर उन पर अवैध कब्जे करा कर उन्हें जड़-मूल से समाप्त कर दिया। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने बड़ी 'मेहनत' करके उन लुप्त हो चुके जोहड़ों को खोजा है। वाकई बड़ा 'कठिन' रहा होगा उनको ढूंढना जिन्हें खुद निगम अधिकारियों ने ही बेच खाया था।

फ़िलहाल ऐसे 4 तालाब विधायक सीमा त्रिखा के विधानसभा क्षेत्र बड़खल में चिन्हित किये गये हैं। इनके उद्धार पर दो करोड़ खर्च करने का बजट बनाया जा रहा है। सर्वविदित है कि जोहड़ों के उद्धार के लिये उनकी खुदाई कराई जाती है। शहर में खुदाई का काम वे लोग स्वयं कर लेते हैं जिन्हें कहीं-कहीं भरत करने के लिये मिट्टी की जरूरत होती है। लेकिन निगम अधिकारी जो स्मार्ट सिटी कम्पनी के अधिकारी भी हो गये हैं, इसी काम पर करोड़ों के खर्चे डाल कर डकारेंगे।

एक बात और भी सामने आ रही है कि उन तालाबों में पानी कहां से आयेगा? जिस वक्त जोहड़ बनाये गये थे व शहर या गांव की सबसे निचली जगह पर बनाये गये थे जहां सारी आबादी का बरसाती पानी बहकर उन में चला जाता था। जब जोहड़ सूखने को होते थे गांव के कुम्हार बर्तन बनाने के लिये तथा मकान के लिये ईंट बनाने के लिये मिट्टी निकालते थे जिससे जोहड़ की खुदाई हो जाया करती थी। लेकिन इस शहर में तो बरसाती पानी को जोहड़ों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। केवल सीवर व नालियों का सड़ा पानी ही इन जोहड़ों को असहनीय हद तक सड़ायेगा।

मजे की बात तो यह है कि एक ओर तो बड़खल झील के तल पर महंगे रसायनों का लेप करा कर पानी को रिसने से रोकने की बात चल रही है, वहीं दूसरी ओर भूमि में पानी रिसाने के लिये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम व तालाबों की बात चल रही है। कुल मिला कर लब्बोलुआव यह है कि इन हरामखोर रिश्वतखोरों ने करना-कराना कुछ नहीं केवल स्मार्ट सिटी के नाम पर आने वाले अरबों रुपये डकारने हैं।

ओल्ड रेलवे स्टेशन:पुलिस संरक्षण में ऑटो वालों की गुंडागर्दी

फ़रीदाबाद (म.मो.) मामला पहली अक्तूबर का है। करीब साढे बारह बजे सचखंड एक्सप्रेस आकर स्टेशन पर रूकी। एनएच पांच के कुछ यात्री शिरडी धाम की यात्रा से लौटे थे। उनके आने की अग्रिम सूचना के चलते उनको लेने उनकी अपनी गाड़ियां आ गई थी।

स्टेशन से बाहर निकलकर जब ये लोग अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठकर घर जाने लगे तो कुछ ऑटोवालों ने अपने ऑटो इन गाड़ियों के सामने अड़ा दिये। ऑटो चालकों का कहना था कि यहां से सवारी उठाने का अधिकार केवल उनके पास है। इस अहाते में किसी भी गाड़ी का प्रवेश वर्जित है यानी कोई गाड़ी यहां प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने ऑटो यहां तक लाने के एवज में जीआरपी (रेलवे पुलिस) को बाकायदा मंथली देते हैं। मंथली के अलावा इनकी फ़टीकें भी भुगतते हैं। इसलिये यहां से वे किसी भी गाड़ी को सवारी नहीं उठाने देंगे।

यात्रा से लौटे कार सवारों ने ऑटो वालों को बहुत समझाया कि यह हमारी अपनी गाड़ियां है न कि कमर्शियल। इसलिये हमें अपनी गाड़ियों में जाने से न रोका जाय। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहा-सुनी गर्मा-गर्मी में बदल गयी। शराब के नशे में धुत दो-तीन ऑटो वालों ने कहा कि वे फतेहपुर चंदीला (स्टेशन के सामने स्थित) गांव के रहने वाले हैं। वे तुम जैसे पंजाबियों से निपटना खूब अच्छी तरह जानते हैं। यह कहते हुये उनमें से एक ने एक कार सवार को एक थप्पड़ जड़ दिया व अन्य दो कारों के शीशे तोड़ने लगे। घटना की उग्रता को देखते हुये यात्रियों में से किसी ने 100 नम्बर पर फ़ोन कर दिया। इसी बीच गर्मा-गर्मी मार पिटाई का रूप ले चुकी थी जो करीब ढाई घंटे तक चली। यात्री भी संगठित थे लिहाज़ा उनसे भिड़ गये और ऑटो वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इसके बाद वे आराम से अपने घरों को चले गये।

इतना सब कुछ हो गया लेकिन न तो जीआरपी वाले थाने से बाहर निकले और न ही 100 नम्बर से कोई आया। विदित है कि स्टेशन से थाना एनआईटी महज 200 मीटर के फ़ासलें पर स्थित है। करीब तीन बजे 100 नम्बर से पुन: घटना की जानकारी फ़ोन करने वाले से मांगी गयी तो उसने भी जवाब दे दिया कि जो होना था वो हो गया। जनता ने अपना झगड़ा खुद ही निपटा लिया।

बड़खल झील के नाम पर 50 करोड़ डकारने का जुगाड़ तो हो गया

फ़रीदाबाद (म.मो.) क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा चुनाव लड़ने से लेकर आज तक बड़खल झील को भरने का सपना दिखाती आ रही हैं। अब 4 साल बाद बताया जा रहा है कि इसे सीवर के पानी से भरने के लिये 50 करोड़ रुपये तो आ चुके हैं, बाकी ज्यों-ज्यों खर्च बढता जायेगा। और फ़ंड आता रहेगा।

आजकल आईआईटी रूड़की के इन्जीनियरों की एक टीम इस सूखी झील में यह तलाश रही है कि कहां-कहां इसका तल कठोर है और कहां-कहां नरम है। जहां नरम होगा वहां से पानी नीचे धरती में चला जायेगा इसे रोकने के लिये उन जगहों पर विशेष लेप लगा कर पानी को नीचे रिसने से रोका जायेगा यानी कि भूजल स्तर को बढाने के लिये रीचार्ज नहीं होने दिया जायेगा।

उक्त बजट में से 30 करोड़ का खर्च सेक्टर 21 में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने व वहां से पाइप लाइनों द्वारा ट्रीटिड पानी को झील तक लाने के लिये होगा। शेष 20 करोड़ से झील की सफ़ाई की जायेगी। यानी यह रकम सीधे-सीधे डकारी जायेगी। रही बात एसटीपी व पाइप लाइनों की तो उसके जीते-जागते उदाहरण आज भी इस शहर में मौजूद हैं। तिगांव रोड पर गांव मिर्जापुर के निकट लगे एसटीपी को देखा जा सकता है। इसकी वजह से न केवल गांव वालों का जीना दूभर हो गया है। बल्कि तिगांव रोड पर चलने वाले भी दुर्गंध से परेशान हैं। वहां सैंकड़ों एकड़ ज़मीन में सीवेज का पानी बीसियों बरस से सड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एसटीपी द्वारा जो पानी ट्रीप यानी साफ़ किया जाता है वह आधा-अधूरा सा ही साफ़ होता है। इसके अलावा अधिकांश सीवेज खराब पाइप लाइनों की वजह से वहां तक पहुंचने की बजाय गुड़गांव या आगरा नहर में ही समा जाता है। लगभग यही स्थिति शेष दोनों प्लांटों की भी है।

इन उदाहरणों से बखूबी समझा जा सकता है कि बड़खल झील के लिये बनने वाला एसटीपी क्या गुल खिलायेगा और पानी को झील तक ले जाने वाली पाइपलाइन कितनी कामयाब होगी। इसका दूसरा उदाहरण आये दिन लीक होने वाली पेयजल की पाइप लाइनों में भी देखा जा सकता है। रैनीवैल से आने वाली पाइपलाइन हो या लोकल सब का यही हाल रहता है तो इस झील के लिये बनने वाली पाइपलाइन कैसे ठीक चल पायेगी। इसके अलावा पम्पिक स्टेशन की जो मोटरें फुका करेंगी वे अलग से। कुल मिला कर हरामखोरों व रिश्वतखोरों के कमाने खाने का एक नया धंधा जरूर शुरू हो जायेगा।

बरसाती पानी क्यों नहीं लाते झील में?

सामने आ रही 50 करोड़ी योजना पर जो खर्च होगा सो होगा, उसके बाद भी लगातार यहां पानी लाने पर जो खर्चा हमेशा होता रहेगा वह अलग से। इस सबके बावजूद जो उपयोगिता बरसाती पानी की हो सकती है वह उस सड़े हुए पानी की नहीं हो सकती।

यह कोई सोचना समझना नहीं चाहता कि बरसों से जो बरसाती पानी इस झील में आता था वह कहां चला गया? सरकारी संरक्षण में अंधा धुंध खनन के चलते, झील की ओर पानी को लाने वाले चैनल बंद हो गये। कुछ पानी इस क्षेत्र में बनी नई झीलों में एकत्र होने लगा तो कुछ बुढिया नाले व अन्य नालों द्वारा इधर-उधर फ़ैलने लगा। यदि जनहित एवं पर्यावरण के बारे में सोचने वाला शासन व प्रशासन होता तो उसी बरसाती पानी को चैक डैम बना-बना कर बरसाती पानी को ब्यर्थ बह जाने से रोकता; झील की ओर जाने वाले बंद चैनलों को खोलता। इस सारी प्रक्रिया से न केवल बड़खल झील शुद्ध बरसाती पानी से लबालब भरती बल्कि पूरे शहर के लिये बहुत ही कम लागत पर विशुद्ध पेयजल उपलब्ध होता। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ियों पर बरसने वाले पानी को यदि संरक्षित किया जाये तो यह न केवल फ़रीदाबाद बल्कि गुड़गांव तक ही पेयजल समस्या का समाधान हो सकता है।

अवैध बसों को पकड़ने पर लगी फ्लाईंग स्क्वायड व सीआईडी पुलिस

क्या ज़िला पुलिस व आरटीए केवल मंथली उगाहने को हैं?

पलवल/बल्लबगढ (म.मो.) पिछले काफ़ी समय से बिना परमिट लिये बड़ी संख्या में अवैध बसें इस क्षेत्र में चलती आ रही हैं। हरियाणा रोडवेज़ जैसा रंग-रूप बना कर ये बसें मथुरा, भरतपुर, अलीगढ व अलवर आदि से पलवल, बल्लबगढ तक तो धड़ल्ले से चलती ही हैं, कुछ बसें दिल्ली तक भी मार करती हैं। ये बसें तमाम कायदे कानूनों का तो उल्लंघन करती ही हैं, साथ में भारी मात्रा में यात्री कर की भी चोरी करती हैं। इनका परिचालन इस ढंग से सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी रोडवेज़ बसों को न के बराबर ही सवारियां मिल पाती हैं। जाहिर है इसके चलते पहले से ही आकंठ घाटे में डूबे परिवहन को भारी घाटा लग रहा है तथा यात्रियों के लिये भी यात्रा जोखिम भरी रहती है।

जानकार बताते हैं यह सारा मामला मुख्यमंत्री विंडो के माध्यम से जब खट्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने फ़्लाईंग स्क्वायड व सीआईडी वालों को उसकी जांच एवं रोक-थाम के आदेश दिये। आदेश पर अमल करते हुये दोनों टीमों ने पुलिस अधीक्षक सीआईडी के नेतृत्व में कई बार अभियान चलाया। दर्जनों बसों को कब्ज़े में लिया। पलवल के विभिन्न थानों व मुंडकटी चौकी में उन्हें बंद किया। इस कार्यवाही के बाद आरटीए द्वारा जुर्माने लगा कर उन्हें छोड़ दिया जाता। छूटते ही वे फ़िर से सड़कों पर लौट आती। यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। यदि खट्टर सरकार वास्तव में ही अवैध बसों को लेकर गंभीर होती तो सर्वप्रथम जिला प्रशासन में बैठे पुलिस अधिकारियों व आरटीए की खबर लेती।

यहां महत्वपूर्ण सवाल यह पैदा होता है कि खट्टर सरकार जो काम सीआईडी से ले रही है, क्या वह उसके लिये बनी है? खट्टर सरकार उस ज़िला प्रशासन एवं आरटीए से क्यों नहीं पूछती कि वे आखिर कर क्या रहे हैं? मजे की बात तो यह है कि सीआईडी द्वारा बार-बार पकड़े जाने के बावजूद भी सरकार ने ज़िला प्रशासन/पुलिस एवं आरटीए के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की। यदि समय रहते सरकार ने इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया तो फ़िर सीआईडी भी सीआईडी नहीं रह जायेगी; उन्हें मंथली कड़वी थोड़े ही लगती है, वे भी अपनी सेटिंग कर लेंगे। उस हालत में तो फ़िर खट्टर जी को स्वयं ही सड़कों पर आकर चेकिंग करनी पड़ेगी।